



इन दोनों व्यक्तियों के गले में पत्थर बांधकर पानी में डूबा देना चाहिए। एक दान करने वाला धनिक और दूसरा परिश्रम न करने वाला दिन्द्र - स्वामी विवेकानंद

## फैसले के कई आयाम

प्रदेश की तेलुगुदेश पार्टी के केंद्र में मंत्री तो नहीं रहे मगर फिलहाल एनडीए से नाता बना हुआ है। दो केंद्रीय मंत्रियों ने इसीफा देने और प्रधानमंत्री से मिलने के बाबत जाहिर किया तो उनकी जबान में तल्खी नहीं थी। लेकिन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बारे में शायब ऐसा कहा जा सकता। इसके कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने उसे फोन पर बात की थी। खैर, नायडू के केंद्र से नाता तोड़ने के फैसले के कई आयाम हो सकते हैं। प्रत्यक्ष वजह तो प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का बाबा पूरा न होना बताया गया, लेकिन राजनीति में हमेशा जो सामने दिखता है, वह ज्यादातर बार होता नहीं है। अगर हम नायडू के पिछले कुछ दिनों और खासकर दो दिनों के बयानों पर गौर करें तो इनका कुछ संकेत भी मिलता है। उनका बड़ा गुरेज है कि प्रधानमंत्री उनके फोन का पलट कर जबाब नहीं देते। इसके अलावा यह भी गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर नायडू की प्रतिक्रिया क्या थी। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि विशेष दर्जा देने पर 14वें वित्त आयाम की संस्तुति का उल्लंघन होगा, जिसके मुताबिक सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों और तीन पर्वतीय राज्यों को ही यह दर्जा दिया जा सकता है लिहाजा, जेटली ने विशेष पैकेज देने की पेशकश रखी। मगर नायडू ने इसे ऐसे देखा कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और वादा पूरा करने की बात कर रहे हैं तो वित्त मंत्री ‘लो या होटी’ की भाषा में बोल रहे हैं। यही नहीं, उनके संसद तो यह भी कह रहे हैं कि राज्य भाजपा में जैसा आक्रमक रवैया दिख रहा है, वह उनकी पार्टी के लिए घातक है। राज्य भाजपा के नेताओं के बयान भी ऐसे हैं कि पार्टी को अपने दम पर ज्यादा लाभाधारक स्थिति दिखाने लगी है। इसमें एक दूसरा पहलू तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यह कहकर जोड़ दिया है कि वे गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस तीसरे मोर्चे के पक्ष में हैं और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को इसमें शामिल होने का न्यौता भी दे डाला है। नायडू ने भी विधानसभा में कहा कि समान विचार वाली सभी पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए। कुल मिलाकर यह अगले साल लोक सभा चुनावों के लिए नई सियासी पंतरेवाली लगती है।

## ‘ठोस कचरा प्रबंधन नियम

सर्वेच्च न्यायालय का यह कहना कि ठोस कचरा हमारे लिए परमाणु बम है और राज्य सरकार उनके फटेन का इंतजार कर रही है, एक ऐसी चेतावनी है जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। न्यायालय इस समय देश भर में ‘ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016’ लागू करने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसके लिए सभी राज्यों को नाटिस भेजा गया था एवं जिसमें राज्य कचरा प्रबंधन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं आदि का विवरण देना था। किंतु केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार को एक मंच पर स्प्रेटिनियम का न उपस्थित होना चाहिए। उपर्युक्त काम परकरा का इंतजार कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में न्यायालय की ओर से प्रतिनियम के पूछा जाया था एवं ज्यादा प्रबंधन के लिए किसी को भी उचित ही ठहराना होता है कि यह सफर बर्चेत है कि किसी को भी परवाह नहीं है। हालांकि केंद्र की ओर से ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 से प्राप्त विवरण के बारे में हलफनामा दाखिल किया गया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। न्यायालय में उपस्थित न होने का मतलब है कि आपने केवल खानपूर्ति कर रही है। केवल पर्यावरणविद् ही नहीं, राजनेता एवं बुद्धियों तक के उपयोग की कई योजाएँ भी बनाई हैं। किंतु एस पर अन्यान्य राज्यों की भूमिका अहम है। केंद्र मानविनियम कर सकता है, आवश्यक सहायता मुहूर्या करा सकता है, मगर करना तो राज्यों को ही है। यदि राज्यों को इसकी परवाह नहीं की उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में जबाब देना है तो पिछ कुछ नहीं हो सकता। एक दिन ये ठोस कचरे के देश सब कुछ नियांगे और हमारे पास तब बचने का कोई रासा नहीं होगा। इसलिए न्यायालय की चिंता और राज्यों के खेतों पर नाराजगी बिल्कुल स्वाभाविक है। पर्यावरण आज सभी सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उपर्युक्त करनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी के बाद राज्य सरकारों से सचेत होंगी और अगली सुनवाई के दौरान अपना पूरा विवरण लेकर उपस्थित होंगी।

## सत्संग

### अज्ञानता

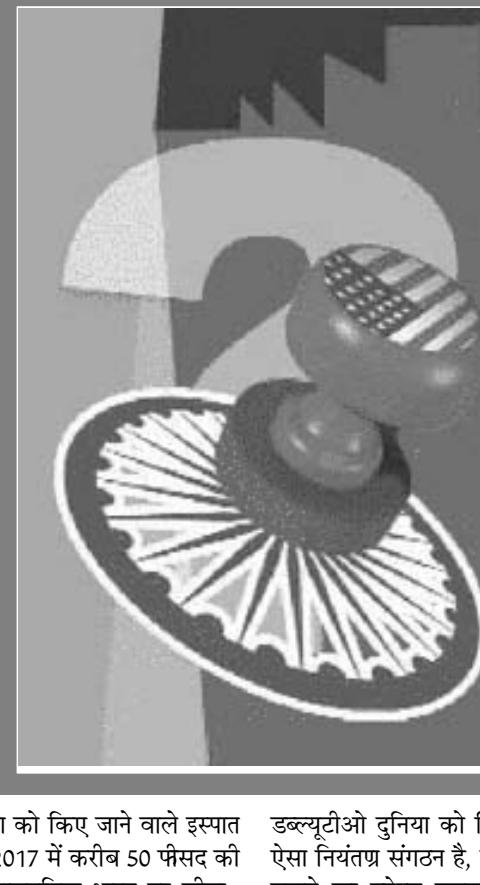
मैं अज्ञानता की बात करता हूं तो मेरा मतलब है कि सब कुछ अज्ञानता ही तो है। हम जिसे ज्ञान कहते हैं, वह भी एक तरह का अज्ञान ही है। हर व्यक्ति अज्ञानता की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर तब तक बढ़ता है, जब तक कि वह किसी आत्मज्ञानी की परम विस्मृति में डूब जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। हर व्यक्ति के लिए अज्ञानता के मायने अलग-अलग होते हैं। तेनालीराम का नाम तो आपने सुना होगा। वह दक्षिण के एक राजा के दरबार में रखते थे। एक बार वह दरबार में कुछ लोगों के साथ बैठे दर्शन पर चंचल कर रहे थे। वहाँ एक आदमी लगातार बैठते रहे तो उनकी साथी करते हैं, वह उनकी साथी करते हैं। जिंदगी एक रहस्य की तरह चलती रहती है। शायद हजारों साल पहले हमें यह भी नहीं पता था कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। अब हम उसे खोलकर देख चुके हैं, उसके साथ काम भी कर चुके हैं। अब हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। लेकिन हम इसके बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, वह उन्हाँ नीरस्यमय होता जा रहा है, पहले से भी ज्यादा। विज्ञान के बारे में माना जाता है कि वह आपके जीवन में स्पष्टता लाता है, लेकिन आज आधुनिक भौतिक विज्ञान ने बहुत सारा भूमि कर दिया है जो रहस्यवाद से भी ज्यादा रहस्यमय लगता है। हमारी समझ और तथाक्षित ज्ञान जितना बढ़ा जाता है, जीवन उतना ही ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा है। ज्ञान-प्राप्ति तो असीमित अज्ञानता को छूता है। हर किसी की अज्ञानता की कोई सीमा होती है, हर बंधन से मुक्त होती है।

## संपादकीय

# नियंत्रण व्यापार युद्ध की नई चिंताओं

ट्रंप लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि अमेरिका के कारोबारी साझेदार विभिन्न देश अमेरिका को कारोबार में भारी घाटा दे रहे हैं। वस्तुतः ट्रंप अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र को संरक्षण देकर उसमें नई जान फूंकना चाहते हैं। उनकी धारणा है कि वैश्वीकरण दुनिया के कई इलाकों में नाकाम साबित हो चुका है और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसान हो जाएगी। भारत को सेवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई में आईटी सेक्टर चमकते हुए पहले क्रम पर है। गौरतलब है कि अमेरिका में लिए एक वर्ष 2019 के लिए एच-1 बी वीजा आवेदन करने का सीजन 2 अप्रैल से शुरू होने का अनुमान है। इस सीजन से ही एच-1 बी वीजा संबंधी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। न केवल अमेरिका में वरन् दुनिया के कई विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को बढ़ावा देने की अत्यमर्द्दी नीति का परिवर्ष भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा संबंधी नुस्खिले बढ़ी हैं। इस तरह अमेरिका सहित विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए इस्पात और एल्युमीनियम नियंत्रित किया।

संतीश पेडणोकर



बढ़ रहा था, उस आईटी उद्योग के लिए अमेरिका व अन्य विकसित देशों के लिए बनाए गए वीजा संबंधी नये नियमों से आगे बढ़ने की तेज गति धीरी हो जाएगी। भारत को सेवा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई में आईटी सेक्टर चमकते हुए पहले क्रम पर है। गौरतलब है कि अमेरिका में लिए एक वर्ष 2019 के लिए एच-1 बी वीजा आवेदन करने का सीजन 2 अप्रैल से शुरू होने का अनुमान है। इस सीजन से ही एच-1 बी वीजा संबंधी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। न केवल अमेरिका में वरन् दुनिया के कई विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को बढ़ावा देने की अत्यमर्द्दी नीति का परिवर्ष भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा संबंधी नुस्खिले बढ़ी हैं। इस तरह अमेरिका सहित विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए इस्पात और एल्युमीनियम नियंत्रित किया। अमेरिका को इस वर्ष 2019 के लिए एच-1 बी वीजा आवेदन करने का सीजन 2 अप्रैल से शुरू होने का अनुमान है। इस सीजन से ही एच-1 बी वीजा संबंधी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। न केवल अमेरिका में वरन् दुनिया के कई विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए इस्पात और एल्युमीनियम नियंत्रित किया। अमेरिका को इस वर्ष 2019 के लिए एच-1 बी वीजा आवेदन करने का सीजन 2 अप्रैल से शुरू होने का अनुमान है। इस सीजन से ही एच-1 बी वीजा संबंधी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। न केवल अमेरिका में वरन् दुनिया के कई विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए इस्पात और एल्युमीनियम नियंत्रित किया। अमेरिका को इस वर्ष 2019 के लिए एच-1 बी वीजा आवेदन करने का सीजन 2 अप्रैल से शुरू होने का अनुमान है। इस सीजन से ही एच-1 बी वीजा संबंधी नियम और सख्त कर दिए गए हैं। न केवल अमेरिका में वरन् दुनिया के कई विकसित देशों में घेरू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए इस्पात और एल्युमीनियम नियंत्रित किया। अमेरिका को इस वर्ष 2019 के लिए एच-1 बी वीजा आव



